The Academia
(A Multidisciplinary Peer-Reviewed Research Journal)
Volume: 03, Issue: I, Pages: 82-87, Year: 2025

ISSN- 2583-8830

भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति: भारत के लिए चुनौती

डॉ. मनोज कुमार यादव [1]

1. सहायक आचार्य, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया (उ0प्र0)

Received: 16 April 2025 **Accepted: 26 June 2025** **Published: 28 June 2025**

शोध सारांश

भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भूटान एक ऐसा पड़ोसी देश है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने में अपना विशेष भूमिका अदा करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 ई. में भारत एवं भूटान के बीच एक द्विपक्षीय मैत्री संधि हुई जिसके अनुसार भूटान के रक्षा एवं विदेश मामलों पर भारत का प्रभाव हो गया । भारत -भूटान के इस मैत्री संधि को चीन स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह न केवल भूटान बल्कि नेपाल, वर्मा और लद्दाख को भी चीन का आंतरिक भाग मानता है ।अपनी इसी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए चीन ने 1950 में तिब्बत पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद से ही भूटान के प्रति प्रेम और दबाव की रणनीति का सहारा लिया है। वह एक तरफ तो भूटान के विकास के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी उसके पास आने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भूटान पर दबाव बनाने के लिए भूटानी क्षेत्र पर अपना दावा भी प्रस्तुत कर रहा है तथा भूटान- तिब्बत सीमा पर सैन्य चौकियों के निर्माण का भी प्रयास कर रहा है ।यही नहीं भूटान- तिब्बत सीमा विवाद का आश्रय लेकर वह भूटानी क्षेत्र पर कई बार अतिक्रमण करने का भी प्रयास किया है जिसके कारण भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य कई बार सैन्य झड़प भी हुई है। डोकलाम विवाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भूटान में किसी भी देश का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए एक चुनौती है। इसलिए भारत एक संप्रभु भूटान की वकालत करता है ।भूटान में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने 1949 ई .के मैत्री संधि की समीक्षा करने के साथ-साथ सभी प्रकार की संभव आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है ।भूटान की जनता को मौसम तथा पर्यावरण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसरो का एक केंद्र भी भारत द्वारा भूटान में खोला गया है। यही नहीं भारत, भूटान के साथ शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, सूचना एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में संपर्क भी बढ़ा रहा है जो उत्तरी क्षेत्र में न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए एक अच्छी इच्छा शक्ति का ज्वलंत उदाहरण भी पेश कर रहा है।

बीज शब्द - अलगाववाद, सिल्क रोड,मोतियों की माला,सीमा विवाद, आर्थिक स्त्रातजिक, आर्थिक पक्षाघात, बल सामरिकी, सीमा प्रबंधन, सैन्य ठिकाने, शरणार्थी, क्रांतिकारी आदि।

1. प्रस्तावना

यह शोधपत्र भारत के पड़ोसी देश भूटान के प्रति चीन की बढ़ती अभिरुचि एवं उसके कारण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ भारत के समक्ष उत्पन्न विकल्पों का विश्लेषण करता है। 1930 ई. में माओ ने खुले मंच से यह घोषणा की थी कि चीन की वास्तविक सीमा के भीतर नेपाल, बर्मा और भूटान तीनों शामिल हैं। 1949 ई. में पब्लिक रिपब्लिक आफ चाइना (PRC) की स्थापना तथा 1950 ई. में तिब्बत पर अधिकार के साथ ही चीन अपनी विस्तारवादी नीति का परिचय देते हुए गाजर एवं छड़ी (Carrot And Stick) नीति को अपनाते हुए एक तरफ बिना शर्त आर्थिक सहायता प्रदान कर भूटान पर अपना प्रभाव स्थापित करने की इच्छा रखता है वहीं दूसरी तरफ तिब्बत -भूटान सीमा पर बलपूर्वक सैनिक चौकिया स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है।साथ ही साथ भूटान- तिब्बत सीमा विवाद को बिना भारतीय हस्तक्षेप के समाधान हेतु दबाव बनाने का भी प्रयास कर रहा है। यह दोनों ही स्थिति भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और विदेश नीति के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। इसलिए यह शोध पत्र कुछ प्रश्नों के समाधान खोजने पर केंद्रित है, जिसमें भूटान में चीनी अभिरुचि के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा विवाद, क्षेत्रीय अखंडता, व्यापार आदि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसके प्रतिउत्तर में भारत को क्या करना चाहिए ? आदि शामिल है ।इस शोध पत्र को कुल तीन खण्डों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड में भूटान- चीन के ऐतिहासिक संबंधों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। दूसरे खंड में चीन द्वारा भूटान को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख है। वहीं तीसरे खंड में भूटान में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के कारण भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियां एवं इससे निपटने के उपाय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

2. शोध प्रणाली

इस शोध पत्र में प्रयोग की गई शोध प्रणाली गुणात्मक शोध तकनीकों पर आधारित है, क्योंकि यह घटना की अंतर-विषयगतता का मूल्यांकन करने में सहायता करती है। डेटा, उपलब्ध साहित्य यानी ऑनलाइन उपलब्ध पुस्तकों और जर्नल, लेखों आदि से एकत्र किया गया है। इसलिए आगमनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है, जहां पहले से निर्धारित शोध प्रश्नों और उद्देश्यों के आधार पर प्रासंगिक डेटा की खोज की गई है। इस शोध के मूल्यांकन के लिए मौजूदा

The Academia
(A Multidisciplinary Peer-Reviewed Research Journal)
Volume: 03, Issue: I, Pages: 82-87, Year: 2025
ISSN- 2583-8830

साहित्य से रूपकों का उपयोग करके भूटान में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ आपसी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावो का विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णन करने के लिए विषयगत विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया गया है। परिणामस्वरूप, एकत्र किए गए डेटा ने भूटान में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता के साथ आपसी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावो से संबंधित विषयों को निकाला है

3. संक्षिप्त इतिहास

चीन के साथ भूटान का प्रथम ऐतिहासिक सम्बन्ध तिब्बत के माध्यम से हुआ। तिब्बत के साथ चीन का प्रथम बार सम्बन्ध चिंग साम्राज्य के अधीन 1720 के दशक से प्रारम्भ हुआ जब चीन का एक राजदूत (रेजीडेन्ट्रस) तिब्बत की राजधानी ल्हासा में रहना प्रारम्भ कर दिया।1 इस समय चीन-भूटान के सम्बन्ध अनौपचारिक थे, क्योंकि इनके औपचारिक सम्बन्धों को लेकर कोई भी साहित्य साक्ष्य के रूप में उपस्थित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भूटान का प्रतिनिधि मण्डल दलाई लामा को साथ लेकर चीनी प्रतिनिधि से मिला था। जब 1865 से 1910 के दौरान भारत और भूटान के मध्य सिन्चुला संधि तथा पुनाखा संधि हुई तो चीन ने पूरे भूटान पर अपना-अपना ऐतिहासिक दावा सिद्ध करने का कई प्रयास किया। 1930 में माओ ने तो खुले मंच से घोषणा किया कि चीन की वास्तविक सीमा के अन्दर वर्मा, नेपाल और भूटान तीनों देश शामिल है।'' उस समय चीन हिमालयन परिसंघ **(HIMALAYAN FEDERATION)** की स्थापना करना चाहता था जिसमें तिब्बत, नेपाल, भूटान के साथ-साथ दक्षिण हिमालय में भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र लद्याख नार्थ इस्ट फ्रान्टियर एजेन्सी **(NEFA)** भी शामिल था। तिब्बत के साथ भूटान की नृजातीय-समानता होने के कारण चीन भूटान पर अपना दावा करता है।

4. भूटान में चीन की बढ़ती अभिरुचि तथा भारत पर उसका प्रभाव :

सन् 1949 में नया चीनी गणराज्य बनने के बाद तो चीन ने पूरे भूटान पर अपने अधिपत्य का दावा किया और गाजर **(Carrot)** और छड़ी **(Stick)** नीति का अनुसरण प्रारम्भ कर दिया। इस नीति के तहत एक ओर तो वह बिना शर्त आर्थिक सहायता तथा बिना भारतीय हस्तक्षेप के सीमा समस्या के समाधान का प्रस्ताव रखा वही दूसरी तरफ पूरे तिब्बत-भूटान सीमा पर सैन्य ठिकानों के निर्माण हेतु भूटान पर दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया। 1950 ई.में तिब्बत पर चीनी अधिपत्य तथा उसके पश्चात् 1959 ई. में तिब्बती क्रांति ने न केवल इस क्षेत्र में एक उलझन पैदा किया बल्कि भूटान को भी अस्थिर कर दिया।2 तिब्बत पर चीनी अधिपत्य के कारण लगभग 6000 तिब्बती शरणार्थियों ने भूटान में शरण लिया जिसके कारण भूटान के सामने सामाजिक-आर्थिक संरचना के साथ-साथ कानून व्यवस्था की भी चुनौती उत्पन्न हो गयी। अधिक शरणार्थियों के आगमन के डर से भूटान ने 1960 के दशक में अपनी उत्तरी सीमा को बलपूर्वक बन्द कर दिया। भूटान की यह कार्यवाही के साथ ही चीन के साथ पुराने सम्बन्धों का अन्त हो गया जिसके कारण भूटानी अर्थव्यवस्था को काफी क्षति हुई।

चीन द्वारा तिब्बत विद्रोहियों के विरूद्ध की गयी हिंसात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप भूटान ने अपने 'अलगाववाद' की नीति को त्याग दिया और भारत के साथ अपने आर्थिक विकास की गति को और अधिक बढ़ा दिया। जिस पर चीन ने अपनी नाराजगी जतायी। 1949 ई. की भारत - भूटान संधि के अनुच्छेद दो में यह व्यवस्था है कि भूटान अपने विदेशी मामलों को भारत के दिशा निर्देश पर ही सुनिश्चित करेगा, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध जताया। प्रारम्भ मे चीन इस संधि का विरोधी था। उसकी पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरह भूटान को भारतीय प्रभाव से अलग किया जाय। चीन हमेशा चाहता है कि भूटान भारत केन्द्रित अपनी विदेश नीति को छोड़कर स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाये। चीन भारत पर यह दोष लगाता है कि उसने भूटान पर अन्यायपूर्ण ढंग से अधिपत्य किया है जिसको वह मुनरो डाक्ट्रिन **(MONROE DOCTRINE)** का भारतीय संस्करण का नाम दिया है। चीन का यह सदैव प्रयास रहा है कि भूटान भारत का विरोधी हो जाय। यदि भारत-चीन के मध्य कोई युद्ध या संघर्ष होता है तो वह चीन का साथ दे और वह भूटान को आधार बनाकर तिब्बत तथा शेष दक्षिण एशिया के साथ अपना व्यापार व व्यवसाय का संचालन कर सके।

समय-समय पर चीन द्वारा प्रकाशित कई मानचित्रों में चीन ने भूटान के विभिन्न क्षेत्रों को अपने भू-भाग के रूप में प्रदर्शित किया है। 1954 ई0 में फारेन लॉग्वेज व्यूरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक **SHORT HISTORY OF MODERN CHINA** में स्पष्ट रूप से सिक्किम, नेपाल और भूटान को चीन का अंग दिखाया गया। इसी प्रकार 1958 में प्रकाशित ऐ अन्य मानचित्र में भूटान के एक बड़े भू-भाग को चीनी अंग के रूप में दिखाया गया। अपनी इस नीति के अधीन 1959 में चीन ने भूटान के 300 वर्ग किमी भू-भाग पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया जिसमें खंगरी, टार्चन, सेकारे, डिराफू, जोंग टूफू, चाकिप, कोचा आदि क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र पर भूटान का लगभग 300 वर्षो से अधिकार था। 1960 ई. मे चीन खुले मंच से पुनः दोहरया कि भूटानी, सिक्कमी और लद्याखी तिब्बत का संयुक्त परिवार है। चीन ने अपने इस विचार को कम्युनिष्ट सिद्धान्त में भी स्थान दिया।

किन्तु 1960 ई. का दशक, विशेष रूप से 1962 ई . के भारत चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास हुए जो भारत-भूटान सम्बन्धों को प्रभवित किया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया में चीन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। 1962 ई . के भारत-चीन युद्ध ने शिक्षित भूटानी नागरिकों के मस्तिष्क में

The Academia
(A Multidisciplinary Peer-Reviewed Research Journal)
Volume: 03, Issue: I, Pages: 82-87, Year: 2025
ISSN- 2583-8830

भारतीय सुरक्षा नीति के प्रति एक आशंका उत्पन्न कर दी जो भूटान की सुरक्षा से सम्बन्धित नयी चुनौती थी। इस स्थिति में भूटान स्वयं को असहाय अनुभव करने लगा था। ऐसी परिस्थति ने निःसन्देह भूटान को प्रेरित किया कि वह भारत केन्द्रित अपनी विदेश नीति को छोड़े और चीन के साथ एक सन्तुलित दृष्टिकोण विकसित करे। सिक्किम की समस्या भी भारत-भूटान सम्बन्धों को प्रभावित करने का एक दूसरा प्रमुख कारण था। भारत में सिक्किम का विलय भी भूटानी शिक्षित नागरिको के मस्तिष्क में भारत के प्रति आशंका पैदा कर दिया। इस घटना के बाद भूटानियों ने यह अनुभव किया कि अपने देश की सुरक्षा उन्हें स्वयं (खुद) करनी चाहिए। इसलिए वह सकरात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए चीन सहित अन्य देशों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने के पक्षधर हो गये।

इस समयावधि में चीन ने तुलनात्मक रूप से सहिषुणता की नीति का पालन करते हुए अपनी दक्षिण-पूर्व एशिया नीति को लागू करने में भूटान को उचित महत्व दिया। इन सब के अतिरिक्त चीन ने यह अनुभव किया कि केवल बल की नीति को अपनाकर भूटान को भारत से अलग नही किया जा सकता। इसलिए भारत द्वारा भूटान के विकास हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता के प्रतिउत्तर में चीन ने बल सामरिकी के साथ-साथ आर्थिक सहायता का भी प्रस्ताव दिया जिसमें पर्यटन सहयोग, जलविद्युत और अधारभूत संरचना एवं संसाधनों का दोहन आदि प्रमुख है। चीन ने यह भी अनुभव किया कि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग जैसे-जैसे बढ़ेगा वैसे-वैसे अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार होगा। परन्तु भूटान ने चीन के इस नीति में कोई रूचि नहीं रखी।

आर्थिक पक्षाघात की स्त्रोतेजी की असफल होने की सम्भावना के कारण चीन ने बल सामरिकी का पालन करते हुए 1966 ई0 में भूटान, चुम्बीघाटी तथा सिक्किम के त्रिमुहानी के साथ-साथ चीनी सैन्य टुकड़ी डोकलाम चरागाह के क्षेत्र में प्रवेश कर गयी। कुछ समय बाद चीन ने औपचारिक रूप से दक्षिणी-पूर्वी भूटान के लगभग 300 वर्गमील पर अपना दावा प्रस्तुत किया जिसमें पुनाखा का उत्तरी क्षेत्र भी शामिल था। पुनाखा 1955 ई0 तक भूटान की औपचारिक राजधानी रही है।3 जब भूटान ने नई दिल्ली से अनुरोध किया कि वह बीजिंग के सामने इस समस्या को उठाये तब चीन ने यह कहते हुए बात करने से मना दिया है कि यह चीन और भूटान का आपसी मामला है और भारत सरकर को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।4 भूटान के पक्ष में भारत द्वारा की गयी लगातार वकालत को अस्वीकार करते हुए चीन ने सीमा पर घुसपैठ की दबाव की रणनीति को अपनाते हुए भूटान को वार्ता हेतु आमंत्रित किया। 1970 ई. के दशक में भारत ने भारत-चीन सम्बन्धों को सामान्य होने संकेत भूटान को दे दिया था जिसके परिणामस्वरूप भूटान के लिए यह सम्भव हो गया कि वह सीमा विवाद मुद्दो पर चीन के साथ सीधा वार्ता कर सके।5 1971 ई . में चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश हेतु भूटानी सदस्यता के पक्ष में मत देकर अपने पक्ष में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया जिसमें चीन-भूटान सम्बन्ध पहले से अच्छे हो गये। संयुक्त राष्ट्र संघ में रिपब्लिक आफ चाइना के उत्तराधिकारी के रूप में पब्लिक रिपब्लिक आफ चाइना (PRC) के पक्ष में भूटान और भारत दोनों अपना मत दिया और सार्वजनिक रूप से एक चाइना नीति का समर्थन किया। 1974 ई0 में जिग्मे सिग्मे वांगचुक के राजतिलक के अवसर पर भूटान ने भारत में स्थित चीनी राजदूत को प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त भूटान के भूमि से तिब्बती शरणार्थियों को बलपूर्वक वापस भेजने के भूटानी निर्णय पर चीन ने भूटान के प्रति सकरात्मक दृष्टिकोण अपनाया। 1959ई0 में लगभग 2000 तिब्बती भूटान में प्रवेश कर गये थे जिसमें कुछ वहॉ रह गये जिसके कारण चीन को शर्मिन्दा होना पड़ा।6 भूटानी सरकार ने यह निर्णय किया कि ऐसे लगभग 400 शरणार्थियों को बलपूर्वक वापस भेजा जायेगा जो भूटानी नागरिकता को अस्वीकार कर दिये हैं। भूटान के इस निर्णय का चीन ने स्वागत किया जिसके कारण भूटान एवं चीन एक दूसरे के अत्यन्त घनिष्ट मित्र हो गये। सीमा विवाद के समाधान हेतु दोनों देशों ने 1981 ई0 में वार्ता प्रारम्भ किया और इसके लिए सीमा आयोग की स्थापना की गयी।7 भूटान के साथ सीधा संवाद चीन के लिए विधिक एवं राजनयिक विजय थी। दूसरी तरफ भारत ने यह तर्क दिया कि भूटान-चीन सीमा विवाद भारत-चीन सीमा विवाद का आन्तरिक भाग है और भारत-चीन सीमा समस्या के समाधान के बिना यह अप्रभावी होगा।

इस संदर्भ में प्रथम औपचारिक वार्ता 1984 ई0 में प्रारम्भ हुई। काफी विचार-विमर्श के बाद नवम्बर 1996 ई0 में चीन ने एक पैकेज डील का प्रस्ताव भूटान के समाने रखा। अन्तर्राष्टीय सीमा आयोग के सचिव दशो प्रेमा वांगचुंग के अनुसार पश्चिमी भूटान मे संचार क्षेत्र विवादित है जो डोकलाभ, सखतो, सिंचुलुम्पा तथा ड्रामन है। चीन ने अपने पैकेज डील के अधीन सीमा विवाद निस्तारण हेतु भूटान के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वह पश्चिमी भूटान के 269 वर्ग किमी भूमि के बदले में मध्य भूटान पसमलुंग तथा जर्करलुंग क्षेत्र के 495 वर्ग किमी भूमि पर अपना दावा छोड देगा।8 पश्चिमी भूटान चुम्बी घाटी के अत्यधिक निकट है जिसकी सिलीगुड़ी कारीडोर से मात्र 500 किमी दूरी है जो भारत के लिए निःसन्देह चिन्ता का विषय है।9 हलांकि चीन और भूटान के बीच कोई समझौता नहीं हो सका क्योंकि भूटान ने इस पैकेज डील को नकार दिया।

दोनों देशों ने 12 चक्र के वार्ता के पश्चात् 8 दिसम्बर 1998 ई0 को सीमा क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में समझौता पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता भूटान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समझौते के द्वारा चीन ने पहली बार भूटान की सम्प्रभुत्ता, स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखण्डता को पूर्णतः स्वीकार किया। यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह पहला ऐसे लिखित विधिक दस्तावेज है जिसमें चीन द्वारा भूटान की सम्प्रभुत्ता को मान्यता दी गयी है। सीमा से सम्बन्धित भूटान-चीन वार्ता में सकरात्मक विकास होता रहा फलतः यह नये युग में प्रवेश कर गया। 23 चक्र के वार्ता के बाद अगस्त 2015 में दोनों देशों ने सीमा

The Academia
(A Multidisciplinary Peer-Reviewed Research Journal)
Volume: 03, Issue: I, Pages: 82-87, Year: 2025
ISSN- 2583-8830

विवाद के अन्तिम निर्णय के पास पहुंच गये। 1128 वर्ग किमी विवादित क्षेत्र को घटाकर 269 वर्ग किमी क्षेत्र तक सीमित कर दिया जो उत्तरी-पश्चिमी भूटान में स्थित है। सीमा विवाद के समाधान हेतु दोनों देशों ने चौबीसवे चक्र की वार्ता हेतु 11 अगस्त 2016 को वीजिंग में एक आयोजन हुआ जिसमें चीन के उप विदेश मंत्री लाऊ जेनमिन ;स्पर्न **(Liu Zhenmin)** तथा भूटान के विदेशमंत्री एल0डी0 डोरजी **(L.D. Dorji)** ने भाग लिया और सीमा विवाद के निस्तारण हेतु गहन मन्त्रणा किया। दोनों मंत्रियों ने अपनी वार्ता से सन्तुष्ट थे। वर्तमान समय भूटान-चीन सम्बन्ध अनवरत एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे है। चीनी सरकार भूटान के साथ अपनी मित्रता बनाये रखने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए वह विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परित सहयोग हेतु हर-समय तैयार है तथा वन रोड एण्ड वन बेल्ट इनिशिएटिव में भी भूटान को भागीदार बनाने को ललायित है।

राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित होने के बाद भूटान ने 2007 ई. में भारत के साथ 1949 ई. में हुई संधि को पुनःनिरीक्षण करने का निर्णय लिया था जिसमें दोनों पक्ष पहले से और अधिक सामानता के आधार पर अपने हितों के अनुसार सहयोग करने पर सहमत हुए। पुनःनिरीक्षण के क्रम में भूटान यह चाहता था कि भारत भूटान से अपनी सेना को हटा ले, क्योंकि भूटान अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारतीय सेना पर निर्भर है। इसलिए वह भारतीय सेना पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता था। भूटान चीन के इस प्रस्ताव पर भी सहमत है कि नेपाल की सीमा की तरह भूटान चीन सीमा को भी असैनिक क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। उसने यह संकेत भी दिया कि वह भारत केन्द्रित विदेश नीति की जगह तथस्थ नीति का अनुसरण करना चाहता है। इसलिए भूटान से भारतीय सेना प्रशिक्षण **(IMTART)** को वह वापस बुलाने पर सहमत है।

वैश्वीकरण, उधारीकरण और राजनीतिक सुधारों ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को वह अवसर दिया कि वह भूटान को प्रभावित करें सके। चीन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भूटान को प्रभावित करने का प्रयास किया और अपने व्यापार को भूटान के साथ बढ़ाया।

चीन को यह विश्वास है कि तिब्बती क्रान्तिकारियों के लिए भूटान एक सुरक्षित स्थान है। तिब्बती, चीनी सेना पर गुरिल्ला आक्रमण के लिए भूटानी जमीन का उपयोग करते है। चीन नहीं चाहता है कि तिब्बती अलगाववादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भूटान लॉचिंग स्थल बने। इसलिए वह भूटान के साथ अच्छा सम्बन्ध बनाकर तिब्बती अलगाववाद के आन्दोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है।

वर्तमान समय में चीन ने ''पश्चिमी विकास नीति'' को स्वीकार करते हुए पूरे हिमालयी क्षेत्र में तिब्बत को केन्द्र बनाना चाहता है। इससे भूटान को यह लाभ होगा कि तिब्बत के साथ भूटान का व्यापार पुनः बहाल हो जायेगा। इस स्त्रातेजी के तहत 21वीं शताब्दी में वह पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रमुख स्थान दे रहा है। यह सर्वविदित तथ्य है कि दक्षिण एशिया में प्रभाव का विस्तार करने की रणनीति का पोषण करते हुए अपने 'मोतियों की माला' की नीति के तहत भारत को घेरने के लिए भारत के तटवर्ती तथा हिन्द महासागर के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इस रणनीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए चीन भूटान को भी अपने समूह में शामिल करने का प्रयास करता रहा है। विगत कुछ समय से चीन हिमालयी क्षेत्र में संचार व्यवस्था के सुधार पर बल दिया है। अरूणांचल प्रदेश के भारत-चीन सीमा के समीप तथा यादोंग चुम्बी घाटी के समीप के साथ-साथ चीन पूरे हिमालयी क्षेत्र में मेगा रेलवे प्रोजेक्टर का निर्माण कर रहा है, जिसका उद्देश्य तिब्बत में संचार व्यवस्था को बढ़ाना जिससे इसका सम्पर्क भूटान सहित अन्य हिमालयी देशो के साथ सरलता से हो सके।

दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक का अदान-प्रदान में भी समयानुसार वृद्धि हो रही है। भूटान एवं चीन के मध्य एक मजबूत संधि बनाने के उद्देश्य से सन् 2005 में पहली बार चीन का सांस्कृतिक दल ने भूटान का भ्रमण किया था। भारत के साथ भूटान के घनिष्ठ सम्बन्धों के प्रतिउत्तर में चीन भूटान के कृषि एवं संचार आधुनिकीकरण में अपना विशेष सहयोग दे रहा है और कृषि तथा संचार उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। चीन भूटान में स्वास्थ, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र में चीन एक बहुत बड़ी राशि निवेश कर रहा है। चीन एक तरफ तो भूटान का आर्थिक सहयोग कर रहा है वहीं दूसरी तरफ दबाव के रणनीति का भी प्रयोग कर रहा है। भूटान को आर्थिक सहायता वास्तव में चीन के ऊपर आर्थिक निर्भरता को बढ़ाने की एक चाल है। भूटान-चीन सीमा पर 470 किमी लम्बी सड़क का निर्माण इसी चलाकी का एक भाग है। यही नहीं भूटान को अपने ऊपर और निर्भर बनाने के लिए चीन ने भूटान के समाने एक ऐसा अवसर उत्पन्न किया है जिसमें वह सिल्क रेल मार्ग के दक्षिणी गलिमारा के तरह वह यूरोप से थाइलैण्ड तक वाया टर्की, ईरान, पाकिस्तान, भारत वर्मा जुड़ सकता है। हलॉकि 1998 के भूटान-चीन सीमाई क्षेत्र में शान्ति एवं प्रशान्ति की बनाये रखने के समझौते के अतिक्रमण करने को लेकर भूटान द्वारा बीजिंग के समाने विरोध जताया गया। परिणामस्वरूप चीन 2003 में सीमा वार्ता तक अपने कार्य को निलम्बित करने को सहमत हो गया। परन्तु कुछ समय बाद सीमापार घुसपैठ(सीमारेख अतिक्रमण) की गतिविधि करना प्रारम्भ कर दिया। चीन के इस गतिविधि को भारत ने ''धमकाने और चिढ़ाने'' की सामरिकी (रणनीति) बताया।

The Academia
(A Multidisciplinary Peer-Reviewed Research Journal)
Volume: 03, Issue: I, Pages: 82-87, Year: 2025
ISSN- 2583-8830

चीन के साथ आने पारस्परिक द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार के बाद भी चीन की बढ़ती घुसपैठ से भूटान असहज है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 2013 में देखने को मिला जब चीनी सेना ने भूटानी भूमि पांगला और संकतेक में न केवल अपना झण्डा लहराया बल्कि अपने शिविर भी लगाये।10 2007 के बाद से चीनी सैनिको ने भूटान-चीन सीमा पर कई मानव रहित चौकियों को भी नष्ट किया है। भूटान के अन्तराष्ट्रीय सीमा के सचिव दासो पेमा बांगचुंक के अनुसार 2009 में चीनी सैनिक लगभग 17 बार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उलंघन कर भूटानी चौकियों पर आये। चीन की घुसपैठ की ऐसी नीति को भूटान पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में माना जा रहा है, जिससे भूटान भारत के प्रभाव क्षेत्र से दूर हो सके और विभिन्न क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दो पर अपना तथस्थ रूख अपना सके।

अभी तक चीन एवं भूटान के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित नहीं सके है परन्तु निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना है। यदि भूटान, चीन को दूतावास खोलने की अनुमति देता है तो इसे बीजिंग को पहली बार इस हिमालयी राज्य में राजनीतिक उपस्थिति मिलेगी। सुनन्दा के दत्ता रे के अनुसर थिम्पू में चीनी उपस्थिति अथवा भूटान-चीन सीमा संधि सिक्किम के पास चुम्बी घाटी त्रिजंक्सन पर भारत की स्थिति को प्रभावित करेगा। दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बन्ध अथवा सीमा का निर्धारण पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप को प्रभावित करेगा।11

5. भारतीय प्रयास:

उपरोक्त विश्लेषण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीन के समकालीन दबाव के बाद भी भूटान भारत के प्रति प्रतिबद्ध रहा है जो कि भारतीय सुरक्षा हितों की रक्षा मे सहायक है। यह सच है कि भूटान की पुरानी पीढिया भारत को कृतज्ञता की दृष्टि से देखती है परन्तु भूटान की नई पीढ़ी भारत के प्रति ज्यादा मुखर होने के साथ-साथ संवेदनशील भी है। भूटान का निजी क्षेत्र **(Private Sectors)** चीन के साथ आर्थिक सम्बन्ध बनाने के लिए भूटानी सरकार पर दबाव बना रहा है। हलॉकि वर्तमान भारत-चीन गतिरोध पर भूटान ने असहजता के साथ भारत का समर्थन किया। भूटान चीन के साथ अपने सीमा विवाद का समाधान चाहता है।

6. निष्कर्ष

भारत,भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों का आकलन अतीत के आदर्शवाद के बजाय वर्तमान के यथार्थवाद पर करना चाहिए। इसलिए भूटान के साथ अपनी विदेशनीति का निर्धारण करते समय भारत, भूटान के राजनीतिक महत्व, स्थानीय आर्थिक व्यवहारिता, व्यापार क्षमता, आतंकवाद विरोधी क्षमता और चीन द्वारा एक प्रमुख आर्थिक एवं सैन्यशक्ति बनने की कोशिश के साथ बनाये गये शक्ति के नये सन्तुलन का भी सम्मान करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत भूटान के साथ शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन सूचना और तकनीकी आदि क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने का कार्य कर रहा है। भारत को भारतीय परियोजनाओं के लाभ को भूटान में प्रचारित करने तथा सहयोग के नये क्षेत्रों को खोजने की आवश्यकता है। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का एक ग्राउण्ड स्टेशन भूटान में स्थापित करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे भूटान को अपने दूर-दराज के क्षेत्रों की मौसम सम्बन्धी जनकारी में सहायता मिलेगी। चीन से सीमा की सुरक्षा दोनों देशों के लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए इस समस्या का समाधान के लिए दोनों देशों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। जैविक खेती, इको पर्यटन सहित कई ऐसे क्षेत्र है जहॉ भारत-भूटान एक साथ कार्य कर सकते हैं। भारत एक तेजी से उभरता हुआ आर्थिक शक्ति है जो सतत् विकास के भूटानी विचारों को अपना सकता है। भारत, भूटान के कार्य क्षमता के निर्माण में हर सम्भव मदद कर रहा है। यद्यपि भूटान बेरोजगारी, राष्ट्रीय ऋण, राजशाही से संसदीय शासन में परिवर्तन आदि के साथ-साथ मध्ययुगीनता से आधुनिकता तक की चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिर भी सहायता प्रदान करके भारत न केवल उत्तरी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की है बल्कि अपने अन्य पडोसियों के लिए एक अच्छी इच्छाशक्ति का ज्वलन्त उधाहरण भी पेश किया है।

7. सन्दर्भ ग्रंथ

- Das, N. (1974). *Dragon country: The general history of Bhutan* (p. 50). Bombay.
- Gulati, C. J. (1990). *Bangladesh: Liberation to fundamentalism* (p. 79). New Delhi.
- Jha, T. (2013, August). China and its peripheries: Limited objectives in Bhutan. *Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS)*, 2.
- Mitra, D. (2010). *Indo-Bhutan relations: Political process, conflict and crisis* (pp. 185, 203). New Delhi.
- Muni, S. D. (1984). Bhutan steps out. *The World Today, 40*(12), 515–516.
- Pal, S. (2022). World Focus, September, 82–83.
- Ramchandran, K. N. (1979, October). Bhutan in focus. *Strategic Analysis, 3*(7), 205.
- Singh, S. (2000). Sino-South Asian ties: Problems and prospects. *Strategic Analysis, 24*(1), 1109–1127.

ISSN- 2583-8830

- Bisht, M. (2010). *Bhutan: Internal developments and external engagements* (p. 19). Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA).
- Bisht, M. (2010, May). Indo-Bhutan relationship: From developmental cooperation to strategic partnership. *Strategic Analysis, 34*(3), 350–353.

Corresponding Author:
डॉ. मनोज कुमार यादव
सहायक आचार्य,
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग,
सतीश चन्द्र कालेज, बलिया (उ0प्र0)
Email: tomanoj1983@gmail.com